PMGKAY का “बेहतर चावल”: टूटे दाने की नई सीमा

कृषि-खाद्य प्रबंधन / कल्याण योजनाएँ | समाचार संदर्भ: PMGKAY के चावल के गुणवत्ता-मानक में बदलाव को CCEA की मंज़ूरी, 1-2 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

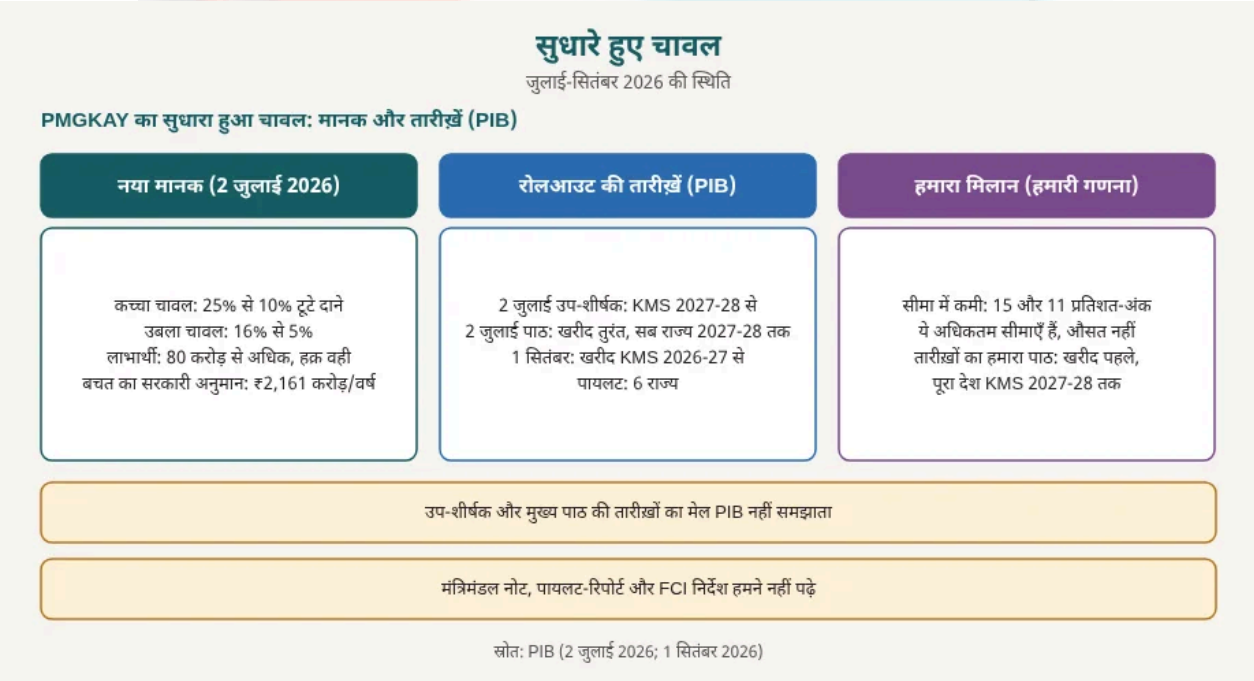
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बँटने वाले चावल में टूटे दानों की अधिकतम मात्रा एक गुणवत्ता-मानक है। PIB (2 जुलाई 2026) के अनुसार PMGKAY और अन्य कल्याण योजनाओं के चावल के मानक लगभग तीन दशक में पहली बार बदले गए। खरीफ विपणन सीज़न (KMS) वह अवधि है जिसके आधार पर धान की सरकारी खरीद की योजना बनती है।

खबरों में क्यों

PIB की 2 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने PMGKAY और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए चावल के गुणवत्ता-मानक में सुधार को मंज़ूरी दी। कच्चे चावल में टूटे दाने की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत और उबले (parboiled) चावल में 16 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है, जबकि लाभार्थियों का हक़ वही रहेगा।

मुख्य अवधारणा: मानक का सुधार, हक़ में बदलाव नहीं

यह सुधार चावल की गुणवत्ता से जुड़ा है, मात्रा या पात्रता से नहीं। PIB के अनुसार पीडीएस के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की मात्रा-पात्रता में कोई बदलाव नहीं है। दूसरी ओर “टूटे दाने की सीमा” अधिकतम सीमा है, औसत नहीं; वास्तविक वितरित चावल में टूटे दाने इससे कम भी हो सकते हैं।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

नए मानक (PIB, 2 जुलाई 2026)	**कच्चे चावल में टूटे दाने अधिकतम 10 प्रतिशत (पहले 25 प्रतिशत) और उबले चावल में अधिकतम 5 प्रतिशत (पहले 16 प्रतिशत)। विज्ञप्ति के अनुसार पीडीएस के मानक लगभग तीन दशक में पहली बार संशोधित हुए हैं। यह सरकार का कथन है।**
टूटे चावल का उपयोग और लागत	पिसाई में निकले टूटे चावल को अलग कर "अन्य उपयोगों" में लगाया जाएगा; विज्ञप्ति के मुख्य बिंदुओं में औद्योगिक उपयोग लिखा है। टूटा चावल मिलर के परिसर से सीधे नीलाम होगा और उसे HDPE बोरों में रखा जाएगा, जिससे जूट के बोरों की ज़रूरत घटेगी। सरकार का अनुमान है कि परिवहन, भंडारण और पैकेजिंग लागत में सालाना लगभग ₹2,161 करोड़ की बचत होगी; टूटे चावल की बिक्री से अतिरिक्त राजस्व की बात अलग से कही गई है।
पायलट और पारदर्शिता	PIB के अनुसार प्रस्ताव को हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में पायलट के रूप में परखा गया। चावल के बोरों पर QR-कोड टैगिंग से आपूर्ति-शृंखला में पता लगाने की व्यवस्था का उल्लेख है।
1 सितंबर 2026 की समीक्षा (PIB, बाद की दिनांकित स्थिति)	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक में "सुधारे हुए चावल" के क्रियान्वयन की समीक्षा हुई। PIB के अनुसार इसकी खरीद KMS 2026-27 से शुरू होकर क्रमशः खरीद करने वाले राज्यों में बढ़ाई जाएगी, राज्यों से मिलिंग क्षमता का आकलन, उन्नयन की योजना और चरणबद्ध रोडमैप माँगा गया, और आंध्र प्रदेश को सुधारे हुए चावल के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन का सम्मान मिला। उसी बैठक में KMS 2026-27 के लिए धान खरीद का अनुमान 708.64 लाख टन तय हुआ।

आँकड़ों और तारीख़ों की जाँच

सीमा में कमी: हमारी गणना: कच्चे चावल में सीमा 15 प्रतिशत-अंक (25 से 10) और उबले चावल में 11 प्रतिशत-अंक (16 से 5) घटी है। ये अधिकतम सीमाएँ हैं, वास्तविक औसत नहीं; PIB में पहले का वास्तविक औसत टूटा-दाना नहीं दिया गया।

रोलआउट की तारीख़: तीन पाठ: 2 जुलाई की विज्ञप्ति के उप-शीर्षक में लिखा है "phased rollout to begin from KMS 2027-28"। उसी के मुख्य पाठ में लिखा है कि खरीद "तुरंत शुरू होगी" और KMS 2027-28 तक सभी खरीद करने वाले राज्यों में चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। 1 सितंबर की विज्ञप्ति में "KMS 2026-27 से खरीद शुरू" लिखा है। हम इन्हें इस प्रकार पढ़ते हैं: खरीद पहले शुरू होगी और पूरे देश में लागू होना KMS 2027-28 तक है, पर उप-शीर्षक का शब्द-चयन इससे मेल नहीं खाता। यह हमारा पाठ है; PIB ने इसे समझाया नहीं है।

₹2,161 करोड़ की बचत: यह सरकार का अनुमान है। विज्ञप्ति बचत के तीन स्रोत (कम परिवहन-भंडारण-संचालन लागत, जूट की जगह HDPE बोरे, मिलर से सीधी नीलामी) बताती है पर उनका अलग-अलग हिसाब और वर्ष का आधार नहीं देती। टूटे चावल की बिक्री का राजस्व इस आँकड़े से अलग बताया गया है।

मानक और हक़: सीमा घटने से टूटे दाने कम होंगे, पर PIB यह नहीं बताती कि इससे मिलों की पिसाई-उपज या चावल की खरीद-लागत पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए हम उस पर कोई निष्कर्ष नहीं देते।

महत्व: खाद्य सुरक्षा से गुणवत्ता की ओर

लाभार्थी की गरिमा और गुणवत्ता: PIB के अनुसार लक्ष्य यह है कि हक़ वही रहे और चावल का दाना बेहतर मिले। गुणवत्ता का लाभ लाभार्थी तक पहुँचा या नहीं, यह फ़ील्ड-स्तर के आँकड़ों से ही पता चलेगा, जो विज्ञप्तियों में नहीं हैं।

मिलिंग और खरीद की तैयारी: 1 सितंबर की विज्ञप्ति के अनुसार राज्यों को मिलिंग क्षमता का आकलन और उन्नयन की योजना बनाने को कहा गया। इससे दिखता है कि सुधार का क्रियान्वयन राज्यों की मिलिंग तैयारी पर निर्भर है।

चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा

मिलों और किसानों पर असर: विज्ञप्तियाँ यह नहीं बतातीं कि कड़े मानक का मिलर, धान खरीद या किसानों पर क्या असर होगा। यह प्रश्न खुला है।

टूटे चावल का बाज़ार: टूटे चावल की नीलामी और औद्योगिक उपयोग की माँग-आपूर्ति के आँकड़े विज्ञप्तियों में नहीं हैं।

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने PIB की 2 जुलाई 2026 और 1 सितंबर 2026 की विज्ञप्तियाँ पूरी पढ़ीं। मंत्रिमंडल का मूल नोट, पायलट-रिपोर्ट, FCI के परिचालन-निर्देश और 1 सितंबर के बाद की प्रगति हमने नहीं पढ़ी। सभी आँकड़े सरकार के दावे हैं।

आगे की राह

इसे 2 जुलाई की मंज़ूरी और 1 सितंबर 2026 की दिनांकित समीक्षा की स्थिति के रूप में पढ़ें। KMS 2026-27 की खरीद के आँकड़े आने पर आकलन बदलेगा।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) अधिकतम सीमा और वास्तविक टूटा-दाना; (2) मंज़ूरी, खरीद की शुरुआत और वितरण का चरण; (3) सरकार का बचत-अनुमान और स्वतंत्र आकलन; (4) PIB के आँकड़े और हमारी गणनाएँ।

मेंस दृष्टि

GS-III: खाद्य प्रबंधन, MSP और खरीद, भंडारण; GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ, PDS सुधार।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

PMGKAY के अंतर्गत वितरित चावल में टूटे दाने की सीमा घटाने के निर्णय के उद्देश्य और संभावित लाभ बताइए। इसके क्रियान्वयन की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और राज्यों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: PDS के चावल का मानक।

मुख्य भाग में: निर्णय: 25 से 10 और 16 से 5; लाभ: गुणवत्ता, लागत, पारदर्शिता; चुनौतियाँ: मिलिंग क्षमता, खरीद-लागत, टूटे चावल का बाज़ार; राज्यों की भूमिका।

निष्कर्ष में: टूटे दाने की अधिकतम सीमा में कमी को मात्रा-पात्रता में बदलाव न मानें; राज्यों की मिलिंग क्षमता, चरणबद्ध खरीद और निगरानी के आधार पर गुणवत्ता-सुधार तथा अनुमानित बचत को परखें।

स्रोत

- PIB, PMGKAY के अंतर्गत सुधारे हुए गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति को मंज़ूरी (2 जुलाई 2026)
- PIB, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य सचिवों का सम्मेलन (1 सितंबर 2026, बाद की दिनांकित स्थिति)

स्रोत: PIB की दोनों विज्ञप्तियाँ पूरी पढ़ी गईं। मंत्रिमंडल का मूल नोट, पायलट-रिपोर्ट और FCI के निर्देश नहीं पढ़े गए।

याद रखें: PIB के अनुसार PMGKAY के चावल में टूटे दाने की सीमा 25 से 10 और 16 से 5 प्रतिशत की गई है, हक़ में बदलाव के बिना। रोलआउट की तारीख़ PIB में अलग-अलग तरह से लिखी है: 2 जुलाई का उप-शीर्षक KMS 2027-28 कहता है, और 1 सितंबर की समीक्षा KMS 2026-27 से खरीद शुरू होने की बात।